

राजस्थान राज्य में लड़कियों के विकास के लिए विभिन्न संगठनों की भूमिका पर एक अध्ययन

Shyokaran Chopra^{1*}, Dr. Manoj Kumar Soyal²

¹ Research Scholar, Faculty of Social Science & Humanities, Maharishi Arvind University, Jaipur, Rajasthan, India

Email: shyokaran Chopra@gmail.com

² Supervisor, Faculty of Social Science & Humanities, Maharishi Arvind University, Jaipur, Rajasthan, India

सारांश- यह अध्ययन भारत के राजस्थान राज्य में लड़कियों के विकास को बढ़ावा देने में विभिन्न संगठनों की बहुमुखी भूमिका का पता लगाता है। यह इस क्षेत्र में लड़कियों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकारी निकायों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) द्वारा की गई पहलों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। यह शोध शैक्षिक कार्यक्रमों, स्वास्थ्य पहलों और कौशल विकास योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण, साक्षात्कार और केस स्टडी सहित गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों का उपयोग करता है। निष्कर्ष लड़कियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच में सुधार करने में इन संगठनों के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करते हैं, जिससे उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। परिणाम राजस्थान में लड़कियों के समग्र विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए कई हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहयोगी दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करते हैं।

खोजशब्द- राजस्थान, लड़कियों का विकास, संगठन, डब्ल्यूडीपी, योजना, शिक्षा

X

परिचय

महिलाओं को समूहों में संगठित करने का महत्व महिलाओं द्वारा निर्मित सामूहिक शक्ति में निहित है, जो उन्हें संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण प्रदान करती है। ये संसाधन उत्पादक परिसंपत्तियों जैसे भूमि, ऋण या मशीनरी के रूप में हो सकते हैं, या स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और विस्तार सेवाओं जैसी सेवाओं के रूप में हो सकते हैं। महिला समूह महिलाओं को बातचीत, कौशल सीखने और अपनी स्थिति में समानता की खोज करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। भारत में महिला विकास ने अब तक महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रमों में सामाजिक कल्याण दृष्टिकोण का पालन किया है। हालाँकि, 1980 के दशक के आधिकारिक दस्तावेजों ने, छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज से शुरू करते हुए, विकास प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करने के इरादे तय किए हैं, लेकिन जिस चीज़ की अनदेखी की गई थी, वह वंचित समूहों के बीच प्राप्ति तंत्र की आवश्यकता थी। इस प्रकार समूह-गठन को इस पत्र द्वारा महिलाओं के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों की प्राप्ति और प्रभावी उपयोग के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाता है। महिला विकास कार्यक्रम राजस्थान में 1984 में छह जिलों में शुरू हुआ था और अब नौ तक फैल गया है। इसे ग्रामीण महिलाओं के बीच जागरूकता निर्माण और समूह गठन के एक केस स्टडी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यह महिलाओं को कल्याणकारी विषयों के रूप में देखने के पैटर्न से अलग है, और अपने परिसर, उद्देश्यों और कार्यान्वयन के संदर्भ में खुद को प्रतिष्ठित किया है। डब्ल्यूडीपी ने स्थापित किया है कि समूहों का गठन संभव है और इसे दोहराया जा सकता है। इसने ग्रामीण महिलाओं के बीच यह अहसास कराया

है कि उनकी वंचित स्थिति अपरिवर्तनीय नहीं है, कि विकल्प मौजूद हैं, कि उनके पास विकल्पों के बीच चयन करने की क्षमता है और वे इस कार्य में अकेली नहीं हैं। डब्ल्यूडीपी जो सवाल उठाता है वह है: महिलाओं को किसके लिए संगठित करें? महिला समाख्या, शिक्षा के लिए महिलाओं को संगठित करने का एक कार्यक्रम है, जिसने उद्देश्यों और जोर में बदलाव के साथ डब्ल्यूडीपी की कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इस प्रकार, डब्ल्यूडीपी में जो प्रासंगिक श्रेणी उभरती है, वह महिलाओं की भागीदारी, बातचीत और संगठन की वह प्रक्रिया है जिसे इसने शुरू किया है।

राजस्थान प्रसंग

राजस्थान उत्तर-पश्चिम भारत में आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है। 34.2 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इसकी जनसंख्या 34.26 मिलियन है। इसके सत्ताईस जिलों में से ग्यारह रेगिस्तानी जिले हैं (थार रेगिस्तान में स्थित), पाँच मुख्य रूप से आदिवासी बहुल हैं और लगभग पंद्रह सूखाग्रस्त हैं। पुरानी समस्याओं में रेगिस्तानीकरण, दुर्लभ, असुरक्षित पेयजल, सूखा और औद्योगिक पिछड़ापन शामिल हैं। राजस्थान अपनी महिला आबादी की कम स्थिति के लिए भी उल्लेखनीय है। राजस्थान में महिला साक्षरता दर 11.4 प्रतिशत है, जबकि अखिल भारतीय आंकड़ा 24.4 प्रतिशत है (अन्य राज्यों के साक्षरता आंकड़ों के लिए अनुलग्नक 2 देखें)। अनुसूचित जाति की केवल 2.69 प्रतिशत महिलाएँ और अनुसूचित जनजाति की 1.2 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं कार्य-सहभागिता की गणना करने के पारंपरिक तरीकों के अनुसार, राजस्थान में महिला कार्य-

सहभागिता दर 21.06 प्रतिशत है। (कार्य-सहभागिता, साक्षरता और लिंगानुपात के जिलेवार विवरण के लिए क्रमशः अनुलग्नक 4, 5 और 6 देखें।) राजस्थान में महिलाओं के पिछड़ेपन के कारण सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों हैं। राजस्थान सामंती राजपूत राजाओं के गढ़ों में से एक था। अन्य सामंती, मार्शल संस्कृतियों की तरह, राजपूतों के बीच भी, समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति ने युद्धरत कुलों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया। राज्य में 1000 महिलाओं पर 1088 पुरुषों का वर्तमान प्रतिकूल लिंगानुपात बताता है कि महिलाओं की निम्न स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में महिलाओं के विकास में इस तथ्य से और बाधा आई कि राजस्थान महिलाओं के उत्थान के लिए आंदोलनों से ज्यादातर अछूता रहा, जिसमें शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और संपत्ति का उत्तराधिकार शामिल है, जिसने 19वीं और 20वीं शताब्दियों में भारत को अपनी चपेट में ले लिया। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन राजस्थान में यह आंदोलन बहुत जोरदार नहीं था और महिलाओं की इसमें बहुत कम भागीदारी थी। अंत में, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक समस्याएं स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच और ईंधन, चारा और पानी की उपलब्धता के मामले में महिलाओं की निम्न स्थिति को और भी जटिल बनाती हैं। राजस्थान के पास जो श्रेय है, वह है दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाली कई गैर-सरकारी एजेंसियां। साथ ही, समुदाय के भीतर से गतिशील व्यक्तियों द्वारा संगठित जमीनी स्तर पर सक्रियता और स्वयं सहायता समूहों की परंपरा है। इसके अलावा, पिछले दो दशकों में अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षेत्र-कार्य में शामिल कई महिला संगठनों का उदय हुआ है। इस तथ्य के साथ कि राजस्थान में एक मजबूत प्रशासनिक लोकाचार है, इसने नवाचार और प्रयोग का मार्ग प्रशस्त किया है।

डब्ल्यूडीपी की पृष्ठभूमि और उत्पत्ति

डब्ल्यूडीपी की शुरुआत राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग (डीआरडीपीआर) द्वारा 1982 से 1984 तक विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के जवाब में किए गए कठोर अभ्यासों के परिणामस्वरूप हुई। डीआरडीपीआर को भारत सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम की देखरेख का काम सौंपा गया था, जिसमें बंधुआ मजदूरी से मुक्ति, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा, बाल टीकाकरण आदि जैसी विभिन्न योजनाएं शामिल थीं। उपलब्ध शोध, गहन क्षेत्र अध्ययन और क्षेत्र में काम कर रही स्वैच्छिक एजेंसियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की समीक्षा करने के बाद, डीआरडीपीआर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए महिलाओं को अभिनव तरीकों से उन तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। आम सहमति यह थी कि एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जो गरीब ग्रामीण महिलाओं में मूल्य की नई भावना पैदा करे और सामाजिक और विकासात्मक मुद्दों के बारे में संचार और समझ के नए मंच विकसित करे। डब्ल्यूडीपी की औपचारिक शुरुआत मई 1983 में की जा सकती है जब विकास आयुक्त ने प्रस्तावित कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त वैचारिक पत्र शुरू किया। इस पत्र पर राज्य प्रशासन के सचिवों और विभागाध्यक्षों ने चर्चा की। इन अधिकारियों को कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं थी, न ही वे इसे लेकर उत्साहित थे। साथ ही, वे राज्य में वित्तीय तंगी को देखते हुए कार्यक्रम के लिए धन देने में भी असमर्थ थे। हालांकि, विकास आयुक्त ने कार्यक्रम के लिए धन जुटाने के बारे में यूनिसेफ और केंद्र के समाज कल्याण मंत्रालय के साथ प्रारंभिक चर्चा पहले ही कर ली थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास और पंचायती राज के प्रभारी मंत्री द्वारा इसकी मंजूरी के

अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव पर राज्य के राजनीतिक नेतृत्व के साथ चर्चा नहीं की गई थी। फरवरी 1984 में, यूनिसेफ ने डीआरडीपीआर द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान के उदयपुर में दो दिवसीय कार्यशाला प्रायोजित की। कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, देश भर से महिला विकास के क्षेत्र के नेताओं और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का महत्व इस तथ्य में निहित था कि परियोजना दस्तावेज के विभिन्न घटकों पर विस्तार से चर्चा की गई और प्रतिभागियों द्वारा सुझाव दिए गए। इसने डब्ल्यूडीपी के लिए बैठकों की सहभागितापूर्ण प्रकृति के लिए भी माहौल तैयार किया।

परियोजना दस्तावेज

उदयपुर कार्यशाला के एक महीने के भीतर ही डीआरडीपीआर ने डब्ल्यूडीपी दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया था। स्थानीय यूनिसेफ कार्यालय के साथ गहन परामर्श करके वित्तीय अनुमान तैयार किए गए थे। दस्तावेज का संक्षिप्त हिंदी संस्करण राजस्थान सरकार द्वारा तैयार और संसाधित किया गया, जिसने अप्रैल 1984 में अपनी अंतिम स्वीकृति दी। दस्तावेज अगले महीने प्रकाशित हुआ। परियोजना दस्तावेज की तैयारी के बारे में दिलचस्प बात इसकी विषय-वस्तु नहीं है, न ही इसके विकास के लिए अपनाई गई प्रक्रिया है, बल्कि इसकी अनंतिम और अस्थायी घोषणा है। वास्तव में, डब्ल्यूडीपी की बैठकों के शुरुआती अभिलेखों में विकास आयुक्त के बयान हैं कि उन्होंने परियोजना दस्तावेज को कोई पवित्रता नहीं दी है, और अनुभव के आधार पर इसके मापदंडों को बदला जा सकता है। वास्तव में परियोजना दस्तावेज संरचना और वित्तीय पैटर्न के लिए अनिवार्य रूप से एक मार्गदर्शक बना रहा। कार्यान्वयन शुरू होने के साथ ही परियोजना के अधिकांश अन्य पहलुओं को बदल दिया गया। इसमें रोजगार और शिक्षा जैसे कार्यक्रम के ठोस उद्देश्यों से हटकर प्रशिक्षण और संचार पर जोर दिया जाना, किसी भी मात्रात्मक लक्ष्य को स्वीकार करने से दृढ़ इनकार और गैर-सरकारी एजेंसियों की बहुत व्यापक भूमिका शामिल थी। परियोजना दस्तावेज में निर्धारित कार्यक्रम के उद्देश्य महत्वाकांक्षी और अस्पष्ट दोनों हैं। महिला विकास रणनीति के लिए दस्तावेज का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह स्वीकार करता है और वास्तव में इस बात पर जोर देता है कि वंचित समूहों, इस मामले में महिलाओं के बीच मजबूत प्राप्ति तंत्र के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। जबकि अन्य कार्यक्रम वितरण प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, डब्ल्यूडीपी का एकमात्र उद्देश्य ऐसे समूह बनाना है जो अपने विकास के लिए खुद को मजबूत करेंगे। यह निहित है कि ये समूह, एक बार बनने के बाद, वह कार्यवाही शुरू करेंगे जिसकी उन्हें आवश्यकता है और जिस पर निर्णय लेंगे। नीति दस्तावेज महिला समूहों की क्षमता में एक बुनियादी विश्वास प्रदर्शित करता है और "महिलाओं के खिलाफ अपमान और भेदभाव के प्रति चिंता व्यक्त करने के लिए एजेंसियों, समूहों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने और बनाने की आवश्यकता है ... (और) ... सूचना, शिक्षा और प्रशिक्षण के संचार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पहचानने और सुधारने में सक्षम बनाना" (जीओआर, 1984)। दस्तावेज का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व महिला समूहों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के लिए कल्पना की गई स्वतंत्रता की डिग्री है। यह मूल रूप से वही है जो डब्ल्यूडीपी को महिला विकास के अन्य अभिनव सरकारी कार्यक्रमों से अलग

करता है। महिला विकास से संबंधित लगभग सभी सरकारी कार्यक्रमों में महिलाओं में जागरूकता और आत्मविश्वास पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, लेकिन डब्ल्यूडीपी से पहले ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था, जिसमें इसे महिलाओं को विकास प्रक्रिया में एकीकृत करने के लिए सर्वोपरि शर्त के रूप में देखा गया हो।

संगठनात्मक आधार

डब्ल्यूडीपी की प्रबंधन संरचना पारंपरिक विभागीय कार्यप्रणाली का एक असामान्य मिश्रण है, जिसमें शीर्ष स्तर की सूचना विकास और संसाधन एजेंसी (आईडीएआरए) के माध्यम से स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की प्रत्यक्ष और निरंतर भागीदारी और समवर्ती मूल्यांकन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई एक एनजीओ, विकास अध्ययन संस्थान (आईडीएस) शामिल है। कुछ हद तक अनोखे तरीके से डब्ल्यूडीपी ने पारंपरिक प्रशासनिक पदानुक्रम के बजाय महिला संगठनों द्वारा निर्णय लेने की पहल को अपने हाथ में लेने की अनुमति दी। बाहरी फंडिंग (यूनिसेफ द्वारा) ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी नियंत्रण तंत्र दिन-प्रतिदिन के आधार पर काम नहीं करते हैं, जैसा कि वे सामान्य सरकारी योजनाओं के मामले में करते हैं। निम्नलिखित चार्ट संगठन और कार्यों के विभिन्न स्तरों को समझने में सहायता करेगा।

स्तर	संगठन/कार्यकर्ता	प्रकार्य
राज्य	महिला, बाल एवं पोषण विभाग	समग्र समन्वय/प्रशासन
	राज्य सूचना विकास एवं संसाधन एजेंसी (आईडीएआरए)- गैर-सरकारी	सूचना, प्रशिक्षण, कर्मचारी चयन, समाचार पत्र
जिला	विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर- स्वतंत्र, गैर-सरकारी निकाय	निगरानी, मूल्यांकन
	जिला महिला विकास एजेंसी	प्रशासन
क्षेत्र	जिला सूचना विकास एवं संसाधन एजेंसी	सूचना, प्रशिक्षण, जिला समाचार पत्र
साथिन	प्रचेता	10 साथिनों के ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता-पर्यवेक्षक, प्रशिक्षक, संपर्क व्यक्ति
स्तर	10 गांवों के लिए एक	समूहों के मुख्य क्षेत्र पदाधिकारी आयोजक/एनिमेटर

राज्य स्तर

मूल रूप से WDP को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग (DRDPR) का एक हिस्सा बनाने का इरादा था। यह उम्मीद की जा रही थी कि एक संयुक्त विकास आयुक्त कुछ सहायक कर्मचारियों के साथ कार्यक्रम का प्रभारी होगा। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, WDP की प्रशासनिक जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग, विशेष रूप से महिला और बाल विकास निदेशालय (W C और N) में स्थानांतरित हो गई। समाज कल्याण विभाग के सचिव को महिला और बाल विकास के एक निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो WDP के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी जिम्मेदार हैं, जिसमें एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम भी शामिल है। उन्हें एक अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो विशेष रूप से WDP के प्रभारी होते हैं। WDP के लिए जिम्मेदार व्यक्ति आम तौर पर एक अपवाद के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की एक महिला अधिकारी रही है। इस पद को IAS अधिकारियों के लिए दूसरे पद पर जाने के लिए एक कदम के रूप में माना जाता है। समाज कल्याण विभाग कर्मचारियों की भर्ती, निगरानी, जिलों के चयन और जिला सूचना विकास और संसाधन एजेंसी (IDARA) के रूप में सेवा करने के लिए एक स्वैच्छिक एजेंसी की पहचान के लिए जिम्मेदार है।

राज्य स्तर पर, सर्वोच्च तकनीकी सहायता एजेंसी या राज्य IDARA भी है। आईडीएआरए की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित थी कि समूह-निर्माण में शामिल कार्य का एक बड़ा हिस्सा समूह की सूचना आवश्यकताओं से संबंधित है। इसलिए, उपयुक्त शिक्षण सामग्री तैयार की जानी चाहिए और उसे लोकप्रिय मुहावरे में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही, सूचना का प्रसार कुशलता से किया जाना चाहिए। आईडीएआरए की जिम्मेदारी क्षेत्र में स्थित स्वैच्छिक एजेंसियों को सौंपी गई है, जो शिक्षा और महिला विकास के क्षेत्र में काम कर रही हैं। राज्य आईडीएआरए जिला आईडीएआरए का समन्वयक है और इसकी भूमिका राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संघ की महिला अध्ययन शाखा द्वारा पूरी की जाती है। राज्य आईडीएआरए के कार्य इस प्रकार हैं:

- जिला और ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों का प्रशिक्षण
- जिला आईडीएआरए कर्मचारियों का प्रशिक्षण
- महिलाओं के मुद्दों से निपटने वाले अधिकारियों और गैर-अधिकारियों से संपर्क
- क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करना कार्यक्रम मूल्यांकन

राज्य स्तर पर तीसरा संगठन विकास अध्ययन संस्थान जयपुर (आईडीएस) है, जिसे मूल रूप से मूल्यांकन एजेंसी के रूप में परिकल्पित किया गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह डब्ल्यूडीपी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण रूप से शामिल रहा है। आईडीएस सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए एक संस्थान है जिसमें क्षेत्र-कार्य और जमीनी स्तर पर सक्रियता का एक मजबूत घटक है। आईडीएस के साथ-साथ राज्य आईडीएआरए की अतिरिक्त ताकत इस तथ्य में निहित है कि इन संगठनों के महिला विकास विंग का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति असामान्य रूप से प्रतिबद्ध हैं।

निर्णय लेने की प्रक्रिया

राज्य स्तर पर अधिकांश निर्णय, कम से कम परियोजना के पहले दो वर्षों के दौरान, हर 2-3 महीने में समूह बैठकों के माध्यम से लिए गए, जिसमें राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य और जिला आईडीएआरए और आईडीएस की महिलाएँ और डब्ल्यूडीपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से जुड़े लोग शामिल थे। इसके अलावा, कुछ अस्थायी सदस्य भी थे - स्थानीय अधिकारी, देश के विभिन्न भागों में महिला विकास के क्षेत्र में काम करने वाली चुनी हुई महिलाएँ आदि। समूह में आमतौर पर 20-25 व्यक्ति शामिल होते थे। समूह द्वारा चर्चा किए जाने वाले विषय निम्नलिखित थे:

- जिला स्तर पर या आईडीएआरएएस में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का मूल्यांकन
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन और प्रशिक्षण टीमों की पहचान
- कार्यक्रम के प्रसार के बारे में चर्चा
- जिला स्तर पर डब्ल्यूडीपी कर्मचारियों की पारस्परिक समस्याओं का समाधान
- जिला स्तर के डब्ल्यूडीपी कार्यकर्ताओं को सलाह देना कि वे जिला प्रशासन से कैसे निपटें, जो अक्सर परिवार नियोजन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), सामाजिक वानिकी आदि जैसे कार्यक्रमों में लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए डब्ल्यूडीपी कार्यकर्ताओं पर दबाव डालता है।

कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया समूह बैठकों की भूमिका को दर्शाती है। डब्ल्यूडीपी की शुरुआत में, डीआरडीपीआर ने कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन प्रक्रिया तैयार की। यह निर्दिष्ट किया गया था कि भारत सरकार या राजस्थान या किसी स्वायत्त संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या किसी गैर सरकारी संगठन में काम करने वाले व्यक्ति डब्ल्यूडीपी में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। नियुक्ति पर, संबंधित व्यक्ति को अलग-अलग मौद्रिक लाभ, निश्चित कार्यकाल दिया जाएगा, इस स्पष्ट समझ के साथ कि यदि उसका काम संतोषजनक नहीं है तो उसे अल्प सूचना पर इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। एक विशेष चयन समिति भी गठित की गई थी। वास्तव में अपनाई गई चयन प्रक्रिया अलग थी। महिलाओं के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ रखने वाले बड़ी संख्या में व्यक्तियों से उन महिलाओं की पहचान करने के लिए परामर्श किया गया, जिन्हें डीडब्ल्यूडीपी में नियुक्त किया जा सकता था। इन व्यक्तियों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों को, जिन्हें जिला स्तरीय आईडीएआरए चलाने के लिए कमीशन किया गया था, आईडीएआरए में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों के नाम सुझाने के लिए कहा गया था। प्राप्त सुझावों को पहले सरकारी अधिकारियों, आईडीएस और राज्य आईडीएआरए के प्रमुख द्वारा अनौपचारिक तरीके से जांचा गया था। इस प्रकार शॉर्टलिस्ट किए गए व्यक्तियों को ऊपर वर्णित समूह बैठकों में से एक में आमंत्रित किया गया था। बैठक के दौरान, जो आम तौर पर 3 दिन तक चलती थी, उम्मीदवारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया। आम तौर पर, समूह बैठकों में आमंत्रित किए गए तीन में से एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के रूप में उभरा। चूंकि शुरुआती चरणों में विकास आयुक्त, और बाद में समाज कल्याण विभाग के सचिव या डब्ल्यूडीपी के प्रभारी निदेशक

बैठक में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने आईडीएआरए और आईडीएस में सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक परामर्श किया और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए चयन किया। राज्य सरकार ने पद के लिए विज्ञापन और चयन समिति की बैठक आयोजित करने की तकनीकीता देखी, लेकिन वास्तव में चयन समूह बैठक में किए गए थे। नए चुने गए कर्मचारियों को बाद की सभी समूह बैठकों में आमंत्रित किया गया, जो उनके प्रशिक्षण और पेशेवर विकास के लिए मुख्य विधि के रूप में काम करती थी। प्रारंभिक प्रक्रियाओं के इस लंबे विवरण का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि डब्ल्यूडीपी के प्रबंधन ने शुरू से ही लचीली प्रक्रियाओं, गहन चर्चा और प्रतिबद्ध कर्मियों के महत्व के विचारों को कैसे स्थापित किया।

जिला स्तर

प्रत्येक डब्ल्यूडीपी जिले में एक जिला महिला विकास एजेंसी (एमडीएम) है, डीडब्ल्यूडीए एक स्वायत्त निकाय (सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी) है जिसके पास वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां हैं। जिला कलेक्टर डीडब्ल्यूडीए के अध्यक्ष हैं और इसकी सदस्यता में कुछ अधिकारी और कुछ महिलाएं शामिल हैं जो शोधकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता हो सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में डीडब्ल्यूडीए में जिला आईडीएआरए और कुछ ब्लॉक और गांव स्तर के डब्ल्यूडीपी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व भी निर्दिष्ट किया गया है। डीडब्ल्यूडीए के सदस्य-सचिव जिला परियोजना निदेशक (पीडी) हैं। परियोजना निदेशक डब्ल्यूडीपी में एक प्रमुख पदाधिकारी हैं। उनका चयन विशेष चयन नियमों के तहत और समूह बैठकों के माध्यम से किया जाता है। अब तक चयनित पीडी में से सभी महिलाएं हैं। भर्ती से पहले उनके व्यवसायों के संबंध में, दो सरकारी कॉलेजों में व्याख्याता थीं, दो गैर-सरकारी कॉलेजों में व्याख्याता थीं, एक मेडिकल डॉक्टर थी, एक राज्य स्कूल शिक्षा विभाग की अधिकारी थी, और एक ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) में अपनी महिला विकास गतिविधियों पर काम किया था। हालांकि डब्ल्यूडीपी दस्तावेज में यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य सरकार पी.डी. के सहायक के रूप में परियोजना अधिकारी (पीओ) उपलब्ध कराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन कुछ स्थानों पर पी.ओ. नियुक्त किए गए, वहां उन्हें पी.डी. के साथ एक टीम के रूप में काम करना मुश्किल लगा, क्योंकि अंतर-व्यक्तिगत समस्याएं और पी.ओ. की नौकरी की जिम्मेदारी में स्पष्टता का अभाव था। पी.डी. कार्यक्रम की मुख्य समन्वयक हैं और परियोजना दस्तावेज में अनुमान लगाया गया है कि उन्हें "पंचायती राज, निकायों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), विभिन्न सरकारी विभागों, जिला आईडीएआरए और अन्य स्वैच्छिक एजेंसियों के साथ चतुराई और दृढ़ता के साथ काम करना होगा।" उनके पास आधिकारिक बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में एक वाहन और कार्यालय सहायक हैं। दस्तावेज में निर्धारित पी.डी. के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं।

ब्लॉक स्तर के डब्ल्यूडीपी पदाधिकारियों (प्रचेताओं) के चयन में सहायता करना;

- प्रचेताओं के काम की प्रत्यक्ष निगरानी करना तथा यथासंभव ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं (साथियों) के काम की निगरानी करना;
- डीडब्ल्यूडीए तथा उसकी समितियों की बैठकें बुलाना तथा उनके निर्णयों को क्रियान्वित करना;

- जिला आईडीएआरए के साथ मिलकर काम करना तथा उसके साथ साझेदारी का संबंध स्थापित करना;
- डब्ल्यूडीपी को आगे बढ़ाने तथा इसके कार्यान्वयन में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों⁶ की बैठकों में भाग लेना;
- डब्ल्यूडीपी में सहायता करने वाले विभिन्न सरकारी विभागों तथा अन्य एजेंसियों के साथ अनौपचारिक तथा सहयोगात्मक संबंध स्थापित करना;
- जिला परियोजना कार्यालय को कुशलतापूर्वक चलाना;
- डब्ल्यूडीपी के कार्यान्वयन तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं को किस सीमा तक मिल रहा है, इसकी समय-समय पर निगरानी करना।

जिला स्तर पर WDP का दूसरा घटक जिला IDARA है। IDARA के रूप में काम करने वाले चार NGO को वयस्क शिक्षा का अनुभव है, एक कॉलेज शिक्षक शिक्षा में काम करता है, और एक विज्ञान के लोकप्रियकरण में काम करता है। बांसवाड़ा जिले में IDARA नहीं है। प्रत्येक IDARA में दो पेशेवर और सहायक कर्मचारी होते हैं। जिला IDARA के कार्य इस प्रकार हैं:

- साथिनों (ग्राम स्तरीय डब्ल्यूडीपी कार्यकर्ता) का प्रशिक्षण,
- साथिनों के लिए तिमाही में एक बार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम,
- साथिन बैठकों में भागीदारी,
- मासिक समाचार पत्र - "साथिन रो कागद" का प्रकाशन,
- महिलाओं से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार,
- साथिनों को मुद्रित और दृश्य-श्रव्य सहायता सामग्री उपलब्ध कराना।

जिला स्तरीय प्रबंधन प्रणाली एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) जैसे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बनाई गई प्रशासनिक प्रणाली और राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम (एनईपी) के तहत परिकल्पित तकनीकी संसाधन सहायता प्रणाली के तत्वों को जोड़ती है। ग्रामीण विकास प्रशासन के एक हिस्से के रूप में, प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) है, जिसमें एक परियोजना निदेशक सदस्य-सचिव के रूप में है। एनईपी मुख्य रूप से वयस्क शिक्षा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन इकाइयों के साथ शिक्षण/शिक्षण सामग्री के प्रशिक्षण और उत्पादन के लिए एक राज्य संसाधन केंद्र की परिकल्पना करता है। ऊपर वर्णित संगठनात्मक संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ डब्ल्यूडीपी की अवधारणा और विकास में प्रत्येक स्तर पर गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए किए गए प्रयास को दर्शाती हैं।

साथिनों का मूलतः चयन किस प्रकार किया गया, इसका विवरण शायद इस प्रक्रिया को स्पष्ट करेगा। जुलाई 1984 में विकास आयुक्त ने राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संघ (जिसे राज्य आईडीएआरए के रूप में कार्य करने वाली संस्था के रूप में पहचाना गया था) के कुछ

लोगों, कुछ स्थानीय गैर सरकारी कर्मचारियों और राज्य शिक्षा विभाग के कुछ चयनित अधिकारियों को जयपुर जिले के कुछ गांवों का दौरा करने के लिए कहा। चूंकि साथिनों के प्रशिक्षण की तिथि तय हो चुकी थी, इसलिए टीमों को कम समय में चयन करना था। इसलिए उन्होंने साथिनों का चयन करने के लिए अपनी यात्राओं को सड़कों से अच्छी तरह जुड़े गांवों तक ही सीमित रखा। इस प्रकार चयनित 32 साथिनों में से 24 प्रशिक्षण के लिए आई, जिसे एक योग्य प्रशिक्षक (एक गैर-सरकारी व्यक्ति) की सहायता से जल्दबाजी में आयोजित किया गया था। पहले प्रशिक्षण सत्र में कोई भी महिला साथिन के रूप में कार्य करने के योग्य नहीं पाई गई। इसके बाद, खंड विकास कार्यालय के कर्मचारियों की सहायता से पीडी द्वारा साथिनों का चयन किया गया। फिर भी, साथिनों के लिए लगभग सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाद, दो या तीन साथिनों को अनुपयुक्त माना गया और उन्हें नियुक्ति आदेश नहीं दिए गए।

साथिन आज विभिन्न जातियों, शैक्षिक स्तरों, आर्थिक समूहों, वैवाहिक स्थितियों और आयु-समूहों की लगभग 550 महिलाओं का एक विषम समूह है। एक ग्राम पंचायत में केवल एक साथिन हो सकती है। इसलिए, प्रत्येक डब्ल्यूडीपी जिले में औसतन 5000 व्यक्तियों (या 4 गांवों) की आबादी पर एक साथिन होती है। प्रशिक्षण पूरा करने वाली साथिन को 200 रुपये मासिक पारिश्रमिक पर औपचारिक नियुक्ति दी जाती है। अपने प्रशिक्षण के दौरान साथिन को मूल्य, आत्म और संवाद करने की क्षमता का बोध कराया जाता है। वह यह समझना शुरू करती है कि उसे अपने गांव और शायद आसपास के कुछ गांवों की महिलाओं को उनकी दुर्दशा को समझने और अपने लिए बेहतर स्थिति हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम बनाने में नेतृत्व की भूमिका निभानी है। साथिनों को प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं के काम, वैवाहिक और सामाजिक मुद्दों, महिलाओं के शरीर विज्ञान और स्वच्छता, चयनित सरकारी कार्यक्रमों आदि से संबंधित कानूनों के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी दी जाती है। साथिन से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने गांव में महिलाओं का एक समूह बनाए और वह कार्यक्रम की मुख्य कड़ी है।

प्राचतास

प्रचेता का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्यों में पीडी और जिला आईडीएआरए और राज्य डब्ल्यूडीपी निदेशक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अधिकांश मामलों में, जिला कलेक्टर निर्णय को समिति के अन्य सदस्यों पर छोड़ देते हैं। प्रचेता का चयन ज्यादातर स्कूल शिक्षकों में से किया गया है, हालांकि काफी संख्या में महिला ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं और कुछ ग्रामीण नर्सों और एनजीओ कर्मचारियों में से भी चुने गए हैं। प्रचेता के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है और प्रत्येक प्रशिक्षण के बाद, कुछ प्रचेता अनुपयुक्त पाए जाते हैं और उन्हें स्थायी नहीं किया जाता है। प्रचेता को नियमित वेतन मिलता है - प्रचेता के रूप में उनके चयन से पहले उन्हें जो वेतन मिल रहा था, उसमें थोड़ी वृद्धि की जाती है।

प्रोजेक्ट दस्तावेज़ में प्रचेता को कार्यक्रम का "प्रमुख एनिमेटर" कहा गया है। प्रचेता के कार्य हैं:

- साथिन का चयन एवं प्रशिक्षण,

- बैठकों की योजना बनाने, महिला समूहों की आवश्यकताओं का आकलन करने तथा विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई शुरू करने में साथिनों की सहायता करना,
- साथिन रिपोर्टों के अनुवाद, क्लस्टर स्तर की रिपोर्ट तैयार करने तथा डीडब्ल्यूडीए एवं जिला आईडीएआरए को इनका संप्रेषण करने के माध्यम से साथिनों एवं जिला स्तरीय डब्ल्यूडीपी संरचना के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना,
- साथिन बैठकों (जजम) के आयोजन में साथिनों की सहायता करना, तथा यथासंभव अधिक से अधिक ग्राम सभाओं में भाग लेना,
- साथिनों एवं प्रखंड विकास कार्यालय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना,
- विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की कवरेज के बारे में डीडब्ल्यूडीए को सूचित रखना,
- जिला आईडीएआरए एवं डीडब्ल्यूडीए के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने वाली साथिनों के वेतन एवं अन्य सामग्री का वितरण करना।
- प्रचेता के पास सामान्यतः बी.ए. की डिग्री होती है तथा वे किसी गांव अथवा प्रखंड मुख्यालय के निवासी हो सकते हैं। प्रचेता के चयन के लिए मुख्य मानदंड हैं: गांव की महिलाओं के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों और जिला डब्ल्यूडीपी संरचना के साथ संवाद करने की क्षमता,
- पदानुक्रमिक धारणाओं को त्यागने की क्षमता ताकि उनके और साथिनों के बीच कोई बॉस-अधीनस्थ संबंध न हो, - अपने मध्यवर्गीय मूल्यों से खुद को अलग करने की क्षमता,
- दृष्टिकोण में लचीलापन।

महिला समूहों का कार्य

परियोजना दस्तावेज में महिला विकास केंद्र (एमवीके) का शाब्दिक अर्थ महिला विकास केंद्र है, जो गांव स्तर पर डब्ल्यूडीपी का केंद्र बिंदु है। मूल रूप से यह परिकल्पना की गई थी कि प्रत्येक एमवीके के लिए लगभग 400 वर्ग फुट का एक छोटा भवन (प्रस्तावित योजना के लिए अनुलग्नक देखें) बनाया जाएगा। एक एमवीके की कल्पना महिलाओं के लिए एक सतत शिक्षा केंद्र के साथ-साथ सरल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए की गई थी। पिछले 4-5 वर्षों के दौरान, कई स्थानों पर एमवीके भवन बने हैं, लेकिन एक स्थान या केंद्र के संस्थागत परिप्रेक्ष्य ने महिला समूहों के अनौपचारिक नेटवर्क की अवधारणा को जन्म दिया है। केवल कुछ एमवीके भवन ही बनाए जा सके और समूहों को संगठित करने का कार्य डब्ल्यूडीपी के नेताओं को एमवीके की स्थापना पर बहुत अधिक ध्यान देने की तुलना में महिला समूह बनाए जाने चाहिए, यह अधिक प्रासंगिक लगा। महिला समूहों के गठन के उद्देश्य से एक कार्यक्रम में केंद्रीय मुद्दा यह है: कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के बड़े हिस्से तक कैसे पहुंचे? जबकि शुरुआती चरणों में समूहों के गठन के लिए कोई ठोस संरचना की परिकल्पना नहीं की गई थी, जैसे-जैसे कार्यक्रम विकसित हुआ, गांव स्तर पर तीन प्रकार के महिला समूह उभरे हैं। पहला जिले के साथिनों की मासिक बैठक है, जिसे

जाजम कहा जाता है। दूसरा गांव में साथिनों द्वारा आयोजित अनौपचारिक महिला समूह है। तीसरा बातचीत के लिए उभरते हुए, अधिक संरचित मंच है। सूचना-साझाकरण और बातचीत के लिए एक अलग मंच जो डब्ल्यूडीपी के कर्मचारियों को एक साथ लाता है, जिसे 'शिविर' के रूप में जाना जाता है।

जाजम

जाजम साथिनों की मासिक बैठक है, जो उनके द्वारा आयोजित की जाती है और यह सीखने, संवाद करने और अनुभवों को साझा करने का मंच है। यह वह जगह है जहाँ महिलाएँ अपनी सामाजिक या व्यक्तिगत समस्याएँ लेकर आ सकती हैं और समाधान और मदद माँग सकती हैं। यह गायन, नृत्य, गपशप और सूचना प्रसार के लिए भी एक जगह है। "जाजम" शब्द का शाब्दिक अर्थ है फर्श पर बिछाया जाने वाला मोटा बुना हुआ कपड़ा और यह दिलचस्प और महत्वपूर्ण है कि यह शब्द संभवतः शोक के दौरान पारंपरिक प्रथा से लिया गया है जहाँ गाँव शोक संतप्त परिवार के चारों ओर सहानुभूति में इकट्ठा होता है, जाजम पर बैठता है और एकजुटता व्यक्त करता है और मदद की पेशकश करता है। जाजम में चर्चा किए जाने वाले प्रमुख मुद्दे क्षेत्र की विशेष समस्याओं पर निर्भर करते हैं। पिछले 3-4 वर्षों में राजस्थान में बार-बार सूखा पड़ा है, और इसलिए, जाजम में सबसे अधिक चर्चा का मुद्दा सूखा राहत कार्य और महिलाओं की उन तक पहुँच रहा है। चर्चा की गई अन्य विकास समस्याएँ हैं: पानी की पहुँच, स्वास्थ्य, पेंशन, ऋण और सब्सिडी का वितरण, चारा, ईंधन की लकड़ी और भ्रष्टाचार। बलात्कार, बाल विवाह, दहेज, परित्याग, विधवाओं की स्थिति और कई कानूनी मुद्दों जैसे सामाजिक मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया है। जजम डब्ल्यूडीपी में न केवल डब्ल्यूडीपी बल्कि अन्य विकास कार्यक्रमों के बारे में फीडबैक के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभरता है। जजम बैठकों में अक्सर डीडब्ल्यूडीए और आईडीएआरए के कर्मचारी शामिल होते हैं और भविष्य की योजना बनाने में मदद करते हैं। यह जजम में भाग लेने वाले साथिनों और प्रचेताओं के पुनर्प्रशिक्षण के लिए भी एक मंच है। जजम में आईडीएस कर्मचारियों की उपस्थिति आईडीएस को मूल्यांकन के कार्य में सहायता करती है।

अन्य विकास योजनाओं के साथ संबंध

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डीडब्ल्यूसीआरए), सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों के लिए समूह बनाना है। डब्ल्यूडीपी और डीडब्ल्यूसीआरए के समन्वय के बारे में कुछ चर्चा हुई है। भीलवाड़ा जिले में प्रायोगिक आधार पर डब्ल्यूडीपी, डीडब्ल्यूसीआरए और एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के अभिसरण का प्रयास किया गया था, जिसके उत्साहजनक परिणाम मिले थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला विभाग) की उप-समिति ने डब्ल्यूडीपी के कामकाज पर रिपोर्ट दी थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (आईसीडीएस के तहत गांव स्तर पर खाद्य पूरक, टीकाकरण और बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए आंगनवाड़ी के प्रभारी) और ग्राम सेविका (डीडब्ल्यूसीआरए के तहत समूहों के गठन के लिए सुविधाकर्ता) को आमंत्रित किया जाता है और वे नियमित रूप से साथिन की बैठकों में भाग लेती हैं। साथिन डीडब्ल्यूसीआरए समूहों के गठन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। पंद्रह साथिन वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र चलाती हैं। भीलवाड़ा के सुवाना गांव में एक उदाहरणात्मक मामले में,

साथिन समेत 12 महिलाओं ने डीडब्ल्यूसीआरए के तहत हथकरघा बुनाई का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने करघा, कच्चा माल खरीदा और खुद ही मार्केटिंग शुरू की, क्योंकि उन्हें पंचायत समिति और डीआरडीए कठोर और बेकार लगे। हालांकि बुनाई अभी तक उनकी आय का प्राथमिक स्रोत नहीं बन पाई है, लेकिन ये महिलाएं अब औसतन 9 से 10 रुपये प्रतिदिन कमा लेती हैं। जोधपुर जिले में, डब्ल्यूडीपी समूह आईसीडीएस केंद्रों को खाद्य पूरकों की प्रक्रिया और आपूर्ति करते हैं। साथ ही, 44 साथिन वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों में प्रशिक्षक के रूप में काम कर रही हैं चक्रवर्ती (1988), डब्ल्यूडीपी और डीडब्ल्यूसीआरए के तुलनात्मक मूल्यांकन में, वास्तव में डब्ल्यूडीपी जैसे कार्यक्रम के साथ डीडब्ल्यूसीआरए को बदलने का सुझाव देते हैं, जिसमें एक प्रमुख फोकस जोड़ा जाता है - डब्ल्यूडीपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आय-उत्पादक योजनाओं को सुविधाजनक बनाना। डब्ल्यूडीपी (93,000 रुपये) के लिए प्रति ब्लॉक उनकी अनुमानित लागत डीडब्ल्यूसीआरए (180,000 रुपये से अधिक) की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा, डब्ल्यूडीपी ने डीडब्ल्यूसीआरए की तुलना में गरीब और निचली जाति की महिलाओं तक पहुंचने में बहुत बेहतर काम किया है। साथिन और प्रचेता के लिए प्रशिक्षण घटक अधिक गहन है और वे डीडब्ल्यूसीआरए के तहत ग्राम सेविकाओं की तुलना में समूह बनाने के लिए बेहतर तैयार हैं।

स्वास्थ्य

महिला स्वास्थ्य का मुद्दा विभिन्न मंचों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बैठकों में महिला समूहों द्वारा चर्चा का विषय रहा है। जानकारी की इस आवश्यकता के जवाब में, अजमेर जिले की महिलाओं के बीच महिलाओं की मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था। इसके बाद फरवरी 1986 में अजमेर में स्वास्थ्य पर एक शिविर आयोजित किया गया। शिविर की सफलता और जानकारी की आवश्यकता को देखते हुए, अजमेर, जयपुर और जोधपुर में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए एक व्यापक परियोजना शुरू की गई। स्वास्थ्य परियोजना विशेष रूप से महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य पर केंद्रित थी, न कि केवल प्रसव के दौरान उनकी भलाई पर। इसने महिलाओं की विशेष समस्याओं जैसे बांझपन, विधवाओं की अपने पति के परिवार के पुरुषों के साथ यौन संबंधों की वास्तविकता और ऐसी महिलाओं की गर्भनिरोधक तक पहुंच के सवाल पर भी ध्यान दिया। पहला कदम महिलाओं की शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान पर एक सरल पुस्तक तैयार करना था। इसकी सामग्री को महिला स्कूल शिक्षकों, अकाल राहत स्थलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से महिलाओं के साथ साझा किया गया। इसके बाद गाँव में इसके स्वागत के बारे में साथिन और प्रचेताओं से गहन चर्चा और प्रतिक्रिया हुई। त्रि-आयामी मॉडल और दृश्य सहायता का व्यापक उपयोग किया गया। अगला कदम गर्भावस्था और नसबंदी पर क्रमशः दूसरी पुस्तक का प्रकाशन था। इन्हें विषय-वस्तु के साथ-साथ सूचना संचारण में बेहतर कौशल के कारण बहुत अधिक उत्साह के साथ प्राप्त किया गया। स्वास्थ्य परियोजना के परिणाम यह थे कि कई और बांझ दंपतियों ने उपचार की मांग की। टेटनस टॉक्सॉयड इंजेक्शन लेने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई, कुछ गर्भवती महिलाओं ने दही और छाछ जैसे पारंपरिक रूप से वर्जित भोजन खाना शुरू कर दिया, पुरानी पीठ दर्द और योनि स्राव वाली कुछ महिलाओं ने उपचार की मांग की, जिनमें से दो को गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर पाया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की महिला कर्मचारी सूचना

प्रसार, बैठकों के निमंत्रण और साथिनों के व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से डब्ल्यूडीपी से सीधे जुड़ीं।

डब्ल्यूडीपी और सूखा राहत गतिविधियाँ

राजस्थान में 1983 से लगातार सूखा पड़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सर्वसम्मत मांग "अधिक अकाल राहत कार्य" है। महिलाएं सूखा राहत कार्य स्थलों पर व्यापक भेदभाव और उत्पीड़न की रिपोर्ट करती हैं। डब्ल्यूडीपी ने सूखे, राहत रोजगार के बारे में नियमों और विनियमों और उनके लिए उपलब्ध निवारण के अवसरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए गांव की महिलाओं की जरूरतों पर प्रतिक्रिया दी। 13 शिविरों में से राजस्थान में 1983 से लगातार सूखा पड़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सर्वसम्मत मांग "अधिक अकाल राहत कार्य" है। महिलाएं सूखा राहत कार्य स्थलों पर व्यापक भेदभाव और उत्पीड़न की रिपोर्ट करती हैं। डब्ल्यूडीपी ने सूखे, राहत रोजगार के बारे में नियमों और विनियमों और उनके लिए उपलब्ध निवारण के अवसरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए गांव की महिलाओं की जरूरतों पर प्रतिक्रिया दी। 13 शिविरों में से महिला एवं बाल निदेशालय (1989) के एक नोट में भीलवाड़ा जिले के सुवाणा गांव का मामला बताया गया है जहां स्थानीय पुरुष ठेकेदार ने प्रत्येक श्रमिक से 10 रुपये जबरन वसूले। भगवती नामक महिला ने साथिन से शिकायत की, जिन्होंने प्रचेता, पीडी और कलेक्टर को इसकी जानकारी दी। ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया और मजदूरों को पैसे वापस किए गए। डब्ल्यूडीपी कार्यकर्ताओं के प्रयासों के परिणामस्वरूप, कुछ कलेक्टरों ने महिलाओं को ठेकेदार के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं, जहां भी साइट पर महिला श्रमिकों की संख्या 75% से अधिक है। अकेले बांसवाड़ा में 12 महिलाएं ठेकेदार के रूप में काम कर रही हैं।

डब्ल्यूडीपी और महिलाओं के लिए आय सृजन

उन लोगों के बीच धारणा में अंतर है जो मानते हैं कि आर्थिक घटक WDP का हिस्सा होना चाहिए और उन लोगों के बीच जो मानते हैं कि इस संबंध में निर्णय लेने के लिए महिलाओं और उनके समूहों पर भरोसा किया जाना चाहिए। यह अंतर WDP के पूरे प्रबंधन ढांचे में व्याप्त है। प्रबंधन का एक बड़ा हिस्सा तर्क देता है कि संसाधनों पर महिलाओं के स्वामित्व की दिशा में पहला कदम अपने नियंत्रण को स्थापित करने में सक्षम होने की ताकत हासिल करना है। उनका तर्क है कि यह केवल महिला समूहों की एकजुटता के माध्यम से ही संभव है। राज्य स्तर पर, IDS और राज्य IDARA में महिलाओं ने बाद वाले दृष्टिकोण को अपनाया जबकि अधिकांश राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ यूनिसेफ कर्मियों ने पहले वाले दृष्टिकोण को अपनाने की वकालत की। धारणा में इस अंतर का प्रभाव जिला स्तर पर देखा जा सकता है।

IDARA के कर्मचारी और कुछ PD मात्रात्मक लक्ष्यीकरण के खिलाफ दलील देते हैं, लेकिन अधिकांश जिला कलेक्टर और कुछ PD महसूस करते हैं कि यदि इतनी संभावनाओं वाला कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इसके कुछ ठोस मात्रात्मक परिणाम सामने आने चाहिए। इस क्रॉस-फायर में अक्सर प्रचेता को चोट पहुँचती है। मूल परियोजना दस्तावेज में निर्धारित डब्ल्यूडीपी के उद्देश्यों में बैंकों और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराना, महिलाओं के

लिए स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू करना और अपनी मौजूदा परिसंपत्तियों से महिलाओं के उत्पादन में सुधार करना शामिल है। हालांकि, पहले कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने डब्ल्यूडीपी दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव लाया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने अनुभवों को साझा करने, संचार क्षमता में सुधार, समूह गठन पर ध्यान केंद्रित किया और रोजगार और ऋण जैसे आर्थिक कार्यक्रम क्षेत्रों को कम महत्व दिया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसी को भी साथियों और प्रचेताओं से कुछ खास करने या कोई खास लक्ष्य हासिल करने के लिए कहने का अधिकार नहीं है। जिला प्रशासन और पंचायत समितियों द्वारा साथियों और प्रचेताओं से परिवार कल्याण, बाल टीकाकरण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में मदद करने के लिए कहने के प्रयासों का कड़ा प्रतिरोध किया गया। समय के साथ, साथियों और प्रचेताओं ने इस बात पर जोर देने के लिए पर्याप्त रूप से पुनर्निर्देशित किया है कि महिलाओं को परिवार के आर्थिक मामलों में अपनी बात रखने में सक्षम बनाना आवश्यक है, जिसमें काम और आय के उपयोग से संबंधित मामले और वे किस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं।

महिला समा और शिक्षा के लिए समूह गठन

राजस्थान से परे WDP के अनुभव को दोहराने के प्रयास में, मई 1988 में गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में "महिला समानता के लिए शिक्षा का कार्यक्रम" शुरू किया गया था। महिला समाख्या नामक कार्यक्रम का बजट 7 करोड़ रुपये है, और इसका वैचारिक सार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) से लिया गया है, जो "महिलाओं के सशक्तीकरण में (सरकार की ओर से) सकारात्मक, हस्तक्षेपकारी भूमिका" की आवश्यकता पर जोर देती है। इस नए कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसा तंत्र बनाना है जो महिलाओं को अपने बारे में निर्णयों में अधिक सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा, विशेष रूप से उनकी अपनी शिक्षा और सूचना के नए क्षेत्रों तक पहुँच के क्षेत्र में। "महिला समाख्या" दस्तावेज़ में बताए गए कार्यक्रम घटक, सहायता सेवाएँ और कार्यक्रम कार्यान्वयन संरचना WDP के लिए समान नीति रूपरेखा में बताए गए लोगों की तुलना में बहुत अधिक जटिल और व्यापक हैं। लेकिन दस्तावेज़ अपने मुख्य भाग और प्रारूप में WDP के अनुभव से व्यापक रूप से आकर्षित होता है। महिला समाख्या की स्थापना गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से संसाधन सुविधाओं का एक नेटवर्क बनाने के लिए की गई है। वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा जो लाभार्थी महिलाओं की कथित जरूरतों के प्रति उत्तरदायी है। महिला समाख्या परियोजना की वार्षिक रिपोर्ट में कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण के रूप में देखा गया है, लेकिन इस बात से अवगत है कि, "शिक्षा को हमेशा साक्षरता के साथ भ्रमित किया जाता है।" इसका आधार यह है कि जब महिलाएं न्यूनतम मजदूरी, ऋण, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल होती हैं, तो वे साक्षरता की मांग करने लगती हैं। यह शिक्षा को कौशल सीखने के व्यापक अर्थ में देखता है।

• संगठनात्मक संरचना

महिला समाख्या की संगठनात्मक संरचना WDP के बहुत करीब है। गांव स्तर पर, महिला संघों के महिला गतिविधि केंद्र बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें दो महिलाएं समूह की मुख्य आरंभकर्ता होंगी। महिला संघों की देखरेख एक समन्वयक या सहयोगिनी द्वारा की जाएगी। जिला स्तर पर एक जिला कार्यान्वयन इकाई (DIU) है जो महिला समाख्या सोसाइटी का एक शाखा कार्यालय है और इसमें

एक जिला कार्यक्रम समन्वयक, एक संसाधन व्यक्ति, सहायक कर्मचारी और वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा (AENFE) के लिए जिला संसाधन इकाई शामिल है। जिला कार्यक्रम समन्वयक गैर-सरकारी क्षेत्र से लिया जाता है, और उसे महिला विकास या शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव होता है। DIU जिला स्तर पर सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित और संचालित करता है। यह संसाधन व्यक्तियों को आकर्षित करता है जिन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए काम पर रखा जाता है। DIU राज्य कार्यक्रम समन्वयक और राष्ट्रीय संसाधन समूह के साथ समन्वय करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनके संसाधनों का उपयोग करता है। जिला कार्यान्वयन इकाई के भीतर एक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ है, जो आई और एनएफई प्रशिक्षकों और ग्राम विद्यालय शिक्षकों की प्रशिक्षण और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। अंततः, यह जिलों में स्थापित होने पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की जिला संसाधन इकाई (डीआरयू) बन जाएगी। कार्यक्रम को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए एक जिला संसाधन समूह की स्थापना की जाती है और इसमें एक समिति होती है, जिसकी नियमित अंतराल पर बैठक होती है। राज्य स्तर पर, महिला समाख्या सोसाइटी एक पंजीकृत सोसाइटी है, जिसकी एक सामान्य परिषद होती है, जिसके प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। कार्यकारी समिति कार्यक्रम के वास्तविक प्रशासन से जुड़ी होती है। इसमें शिक्षा सचिव, राज्य कार्यक्रम समन्वयक, जिला कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय संसाधन समूह के नामांकित व्यक्ति और तकनीकी संसाधन एजेंसी के निदेशक शामिल होते हैं। राज्य कार्यक्रम निदेशक संबंधित राज्य में कार्यक्रम का प्रशासनिक प्रमुख होता है। अब तक नियुक्त किए गए दो निदेशकों (गुजरात और कर्नाटक में) में से एक आईएएस अधिकारी हैं और दूसरा स्वैच्छिक क्षेत्र में अनुभव वाला एक गैर-सरकारी व्यक्ति है। दोनों महिलाएं हैं। डब्ल्यूडीपी के अनुभव के बाद, मूल्यांकन को कार्यक्रम की परिचालन रणनीति में अंतर्निहित एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक राज्य में राज्य सूचना प्रशिक्षण और संसाधन एजेंसी (एसआईटीएआरए) के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय संसाधन समूह द्वारा एक स्वैच्छिक एजेंसी या सामाजिक विज्ञान संस्थान का चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कार्यकर्ता महिलाओं आदि से युक्त एक राष्ट्रीय संसाधन समूह की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में कार्यक्रम को निर्देशित करने, समन्वय करने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। एनआरजी प्रत्येक जिले में उपयुक्त स्वैच्छिक एजेंसियों के समर्थन को जुटाने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वयक एनआरजी का सदस्य सचिव है। उन्हें सलाहकार, एक शोध सहयोगी और सहायक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

प्रारंभिक कार्यान्वयन

कर्नाटक और गुजरात में राज्य कार्यक्रम निदेशकों की नियुक्ति की गई है। दोनों राज्यों को 1,10,64,550 रुपये की राशि जारी की गई है। जिला स्तरीय कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश के दो जिलों, गुजरात के एक जिले और कर्नाटक के तीन जिलों में फील्ड कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। महिला संघों की संख्या बढ़ाने या झोपड़ियों के निर्माण की प्रक्रिया जिला स्तरीय ढांचे की स्थापना के बाद ही शुरू की जा सकती है। राज्य स्तरीय

प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना तक नौ गैर सरकारी संगठन शिक्षा मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों ने सहयोगिनियों, महिला संघ समन्वयकों की पहचान करने और उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में मदद की है। कार्यक्रम के शुरुआती कार्यान्वयन में शिक्षा मंत्रालय के सामने आने वाली समस्याओं में से एक कार्यान्वयन के लिए परिकल्पित प्रशासनिक ढांचे से संबंधित है। नोडल राज्य एजेंसी जो एक पंजीकृत सोसायटी थी, द्वारा सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का कोई उदाहरण नहीं था। इसलिए राज्य स्तरीय समितियों के पंजीकरण को सक्षम करने के लिए नियमों में बदलाव करना पड़ा।

निष्कर्ष

राजस्थान में लड़कियों के विकास में विभिन्न संगठनों की भूमिका पर अध्ययन सरकारी, गैर-सरकारी और समुदाय-आधारित संगठनों के समन्वित प्रयासों के महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करता है। इन संस्थाओं ने सामूहिक रूप से लड़कियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति में योगदान दिया है, जो गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करते हैं। सरकारी कार्यक्रमों ने लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों और योजनाओं को लागू करके एक आधारभूत भूमिका निभाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति जैसी पहलों ने स्कूलों में नामांकन दर में सुधार किया है और स्कूल छोड़ने की दर को कम किया है। पोषण, टीकाकरण और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को लक्षित करने वाली स्वास्थ्य पहल भी लड़कियों की समग्र भलाई को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही हैं। गैर सरकारी संगठनों ने जमीनी स्तर पर समर्थन और वकालत प्रदान करके इन प्रयासों को पूरक बनाया है। एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के माध्यम से, ये संगठन राजस्थान में लड़कियों के सशक्तीकरण और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जिससे एक अधिक समतापूर्ण और समृद्ध समाज का मार्ग प्रशस्त होगा। राजस्थान में लड़कियों के विकास में विभिन्न संगठनों की भूमिका पर अध्ययन सरकारी, गैर-सरकारी और समुदाय-आधारित संगठनों द्वारा समन्वित प्रयासों के महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करता है। इन संस्थाओं ने सामूहिक रूप से लड़कियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति में योगदान दिया है, जिससे गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर किया जा सके। सरकारी कार्यक्रमों ने लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों और योजनाओं को लागू करके एक आधारभूत भूमिका निभाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति जैसी पहलों ने स्कूलों में नामांकन दर में सुधार किया है और स्कूल छोड़ने की दर को कम किया है। पोषण, टीकाकरण और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को लक्षित करने वाली स्वास्थ्य पहल भी लड़कियों की समग्र भलाई को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही हैं। गैर सरकारी संगठनों ने जमीनी स्तर पर समर्थन और वकालत प्रदान करके इन प्रयासों को पूरक बनाया है। सामुदायिक जागरूकता अभियान, कौशल विकास कार्यशालाएँ और मेंटरशिप कार्यक्रम जैसे उनके जमीनी स्तर के हस्तक्षेपों ने लड़कियों को सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए सशक्त बनाया है। एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के द्वारा, ये संगठन राजस्थान में लड़कियों के सशक्तीकरण और उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जिससे एक अधिक समतापूर्ण और समृद्ध समाज का मार्ग प्रशस्त होगा।

संदर्भ

1. चटर्जी मीरा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए समूहों का आयोजन: रणनीतियों और प्रभावों पर कुछ विचार, विश्व बैंक, वाशिंगटन डी.सी., 1989.
2. चक्रवर्ती मीनाक्षी, भारत में गरीब महिलाओं तक पहुंचने के प्रयासों का संस्थागत संदर्भ, विश्व बैंक, वाशिंगटन डी.सी., 1988
3. बनरई सुष्मिता, साधिन प्रशिक्षण में संचार के रूप, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर, 1986
4. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला विभाग, डब्ल्यूडीपी के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करने के लिए उप-समिति की रिपोर्ट, राजस्थान, नई दिल्ली, 1988
5. राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, महिला विकास परियोजना, जयपुर, 1984
6. विकास अध्ययन संस्थान, पदमपुरा, जयपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रिपोर्ट, 1984.
7. रॉय अरुणा और जैन शारदा, महिला विकास कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर, कोई तारीख नहीं संकेतित
8. स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, श्रम शक्ति, नई दिल्ली, 1988
9. विश्व बैंक, भारत में लिंग और गरीबी, वाशिंगटन डी.सी. 1989

Corresponding Author

Shyokaran Chopra*

Research Scholar, Faculty of Social Science & Humanities, Maharishi Arvind University, Jaipur, Rajasthan, India

Email: shyokaran Chopra@gmail.com